20.02 hrs.

MOTION RE: FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): सभापति महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं :

"That this House takes note of the statement laid on the Table by the Minister of Irrigation and Power on the 14th November, 1967 on the flood situation in the country."

हमारे देश में बाढ़ एक एनुअल फीचर हो गई है। हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ आती है और उस के साथ अकाल भी पड़ता है। बाढ़ से लोगों को बहुत तक्लीफ़ होती है और बहुत नुक्सान उठाना पड़ता है। बाढ़ के कारण कितना एक्सटेंसिव डेमेज होता है, मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उसके मुकाबले में बाढ़ों की रोक-थाम के लिए सरकार की तरफ से जो काम होता है, वह बहुत थोड़ा है। ये आंकड़े पिछले दस सालों के हैं। पिछले दस सालों में करीब 13 करोड़ लोगों पर बाढ़ का असर हुआ है, करीब 174 करोड़ एकड़ ज़मीन कभी न कभी बाढ़ से खराब हुई है, जिसमें से 54.7 करोड़ एकड़ ज़मीन फसलों की थी और करीब 69,88,677 मकानों को नुक्सान हुआ है।

इतने लार्ज-स्केल पर नुक्सान होने के बावजूद सरकार बाढ़ के सम्बन्ध में सिर्फ पैचवर्क करती है, थोड़ा सा काम करती है। आज स्थिति यह है कि थोड़ा-सा मेक-शिफ्ट काम हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने एरियल सरवे कर लिया, प्राइम मिनिस्टर्ज़ रिलीफ़ फंड से पच्चीस हजार रुपया दे दिया, फिर पानी उतर गया और सब काम खत्म। जितना बड़ा यह प्राबलम है उसके हिसाब से काम अभी तक नहीं हुआ है। जब तक बाढ़ की रोक-थाम के लिए पर्मानेंट लेवल पर और नैशनल लेवल पर काम नहीं होगा, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

पिछली तीन फ़ाइव-यीअर प्लान्ज़ में बाढ़ की रोक-थाम पर करीब 147 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन उसका लाभ केवल 115 लाख एकड़ ज़मीन को पहुंचा है। सरकार की तरफ़ से अब तक सिर्फ़ कैजुअल एटेम्प्ट्स की गई हैं। उसने अभी तक इस समस्या की कोई पायदार पर्मानेंट सालूशन निकालने की कोशिश नहीं की है। केवल 1955 में 275 लाख एकड़ ज़मीन को बाढ़ से नुक्सान हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया है, पिछले तीन प्लान्ज़ के दौरान, यानी पिछले पन्द्रह सालों में, सिर्फ़ 115 लाख एकड़ ज़मीन को लाभ पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि हम जो काम करते हैं, वह बहुत थोड़ा है, जब कि बाढ़ों से होने वाला नुक्सान बहुत ज्यादा है।

मैं मानता हूं कि हम बाढ़ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और हमें कुछ हद तक नेचर पर डिपेंड करना पड़ेगा, लेकिन क्या सरकार देश को नेचर की दया पर ही छोड़ना चाहती है? जब दुनिया में साइंटिफ़िक तरीके बढ़ रहे हैं, नई-नई ईजादें हो रही हैं, दुनिया के बड़े-बड़े देश ड्राउट और फ्लड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें भी इस बारे में शुरूआत करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले बीस सालों में बाढ़ की रोक-थाम के सिलसिले में काम नहीं के बराबर ही हुआ है। मैं इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सारे देश का सरवे कर के यह मालूम करना चाहिए कि बाढ़ के सम्बन्ध में एग्ज़ेक्ट प्राबलम क्या है। इसके बाद प्रायर्टीज़ फ़िक्स करनी चाहिए कि कौन से साल में कौन सी प्रोजेक्ट पूरी की जायेगी। इस काम के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए, ताकि अगले दस बीस सालों में हम अपने देश में बाढ़ों को कंट्रोल कर सकें।

हमारे डिपार्टमेंट्स की इनएफ़िशेंसी की वजह से हमारे प्लान्ज़ की इम्प्लीमेंटेशन समय पर नहीं होती है। वर्षा होती है, बाढ़ आती है और

फ़लड्ज़ को रोकने के लिए जो काम होते हैं, वे सब खत्म हो जाते हैं। अगर हमारे प्लान्ज़ का इम्प्लीमेंटेशन ठीक और समय पर हो, हमारे वर्क्स के डिज़ाइन फ़ाल्टी न हों, यह सब काम करने के लिये एक एफिशेंट मशीनरी का निर्माण हो, तभी यह समस्या हल हो सकती है।

लोगों को बाढ़ के बारे में सूचना देने के लिए आवज़र्वेशन पोस्ट्स बनाई जानी चाहिए। आज स्थिति यह है कि लोगों को बाढ़ के बारे में समय पर पता नहीं लगता है। नैनीताल और पूना में बांध टूटे, लेकिन आस-पास के क्षेत्र के लोगों को पता नहीं चला कि बांध टूटने से बाढ़ का पानी आ रहा है, जिसके परिणाम-स्वरूप सैंकड़ों आदमी मारे गए।

अब तक सरकार ट्रेडीशनल और रुटीन टाइप के फ्लड कंट्रोल मेज़र्ज लेती आई है। दुनिया में इसके लिए नये-नये मेज़र्ज एडाप्ट किये गये हैं, नये-नये डिवाइसिज़ इवाल्व किये गये हैं, लेकिन हमारे यहां कुछ नहीं किया गया है। कुछ देशों ने फ्लड आवज़वर्ज़ की व्यवस्था की है। बाढ़ों की रोक-थाम के लिये नये तरीके और सिस्टम अख्त्यार किये जाने चाहिये, प्रायर्टीज़ फ़िक्स करनी चाहिये और अपने बेसिक आउटलुक को बदलना चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि उस को पहले किस बात पर एम्फ़ेसिस देना है। सरकार बड़े-बड़े डैम बनाती है। लेकिन हर साल फ्लड आने से पहले उन डैम्ज को चैक करना चाहिए कि कहीं उनमें कोई लीकेज या कमज़ोरी तो नहीं आ गई है। हर साल इन डैम्ज का इन्सपैक्शन होना चाहिये। अगर ऐसा किया जाता, तो यू० पी० में जो नानकसागर बांध के टूटने की घटना हुई, वह न होती।

यह भी देखा गया है, कि इन कामों के बारे में स्टेट्स आपस में झगड़ती हैं। हमारे यहां दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में मतभेद है। आवश्यकता इस बात की है कि सब स्टेट्स के को-आपरेशन से फ्लड कंट्रोल की योजनाएं बनाई जानी चाहिएं।

अगर हमारे देश में फ्लड को कंट्रोल कर लिया जाये, तो मैं कह सकता हूं कि फ्लड्स से बजाये नुक्सान के फ़ायदा होगा। एक अमरीकन एक्सपर्ट डा० वटन, ने कहा है कि अगर हिन्दुस्तान इस समस्या को ठीक तरह से सुलझा ले, तो उसमें इतनी पौटेन्शलिटीज़ हैं कि यहां पर कभी अकाल नही पड़ेगा और अनाज के बारे में कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

दिल्ली में पिछले बीस सालों से हर साल बाढ़ आती है और एक ही बारे में चालीस पाचास गांव बह जाते हैं। नजफ़गढ़ नाले की समस्या बीस साल तक कोशिश करने के बाद भी नहीं हल की जा सकी है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस बारे में विचार करें और बाढ़ की समस्या को हल करने के लिये नेशनल लेवल पर प्लान बनायें।

SHRI SAMAR GUHA (Contia): Sir, I wish there had been a Chavan from West Bengal or Orissa for highlighting the havoc caused in Midnapore District and Orissa by floods recenly.

I do not in any way wish to undermine or minimise the sufferings of the Koyna people. But the figures I have got are that 20,000 houses have been damaged and 2 lakh people have been affected in Koyna area. But in the recent floods in Orissa and West Bengal—as regards Orissa, my hon. friend, Shri Kundu, will speak—the havoc wrought has been immensely greater. In Midnapur district alone, more than 12 lakh people have been affected. The figures I am giving are official figures. 85,000 houses have been completely washed away, 1,000 heads of cattle washed away, 12 high schools in my constituency have been completely devastated and 457 primary schools have completely collapsed. Not only that, 3-4 lakh acres of cultivated paddy land have been completely destroyed. This Contai area which supplies pan which is famous all over

[Shri Samar Guha]

India. A few salt factories have also been completely erased. Except a few main roads, all the feeder roads, have been completely obliterated.

This is not all. Crops worth Rs. 25 crores have been damaged. This is not my figure, but the official estimate. You know that part of the Contai sub-division which is my constituency and which is also part of the constituency of our venerable friend, Shri Samanta, —these are the surplus areas in West Bengal. They are known as the granary of the southern side of West Bengal. There is only one crop in a year. It has been completely devastated resulting in a loss of Rs. 25 crores worth of foodgrains. What will happen to these people of flood-affected areas I do not know.

I had sent frantic telegrams to the Prime Minister and the Food Minister to go there at the time of flood and see things for themselves or at least to make a statement. Unfortunately, our Chief Minister was then ill and could not visit that area. As a result, the devastation that occurred there during the recent flood did not get the attention of the nation at large.

What about the relief measures? As a result of drought in West Bengal, Rs. 12 crores sanctioned by the Relief Minister, were completely exhausted. With the result, the West Bengal Government has no money now to spend on relief works. They have sent frantic appeals to the Centre to give aid for relief work. But Central relief did not reach in time. I am getting telegrams and letters about the conditions there and asking for relief. At least for the next three months, we have to give some relief to that area. All the schools have either been destroyed or damaged and students cannot pay their tuition fees to the teachers of colleges and schools. Recently, the West Bengal Government completely stopped all relief measures. As I have already said, the *aman* crop is the only crop in that area. I have been told that 80 per cent of the people have completely lost their only crop, their only means of sustenance. What will happen to them, God alone knows! There is no proper aids, no comprehensive relief measures are forthcoming.

The devastation that has been caused is unprecedented in recent times. During the last 100 years, such a flood had never occurred in the Midnapur district. The root cause of the flood in Midnapur and Orissa is the treacherous Subarnarekha river which had burst over its banks and flooded the whole area. The water flows over to Midnapur and other parts of Contai sub-division. As a result, all of the five basins were flooded. These basins are Dubda, Badhia, South Contai, Magra and Bara Chauka. All these areas become waterlogged as a result of the overflow from Subarnarekha and they usually remain water-logged for whole year due to depression of land in these basins. I would request Government to take some permanent measures to control the flood both in Orissa and also in Midnapur area. Dr. K. L. Rao should immediately visit the place, survey the area and concrete measures to give permanent relief to this area from the devastation of floods be taken. If these waterlogged basins can be reclaimed, not only would we achieve flood control and assure protection to common people from floods but the production of rice in the Contai sub-division and other parts of Midnapur, which are already a surplus area, will be doubled. This will supply the needs of not only Contai and Midnapur but also the rest of West Bengal. I would therefore request Dr. K. L. Rao to immediately visit the area and take permanent measures for flood control and food production there.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, यह बाढ़ की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। हर साल किसी न किसी राज्य में या कई राज्यों में बाढ़ आती है। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक 20 वर्षों की आजादी के बाद भी हम ऐसा कोई

तरीका नहीं निकाल पाये हैं कि बाढ़ का नियंत्रण किया जा सके आप जानते हैं बाढ़ तो देश के विभिन्न राज्यों में आती रहती है। बिहार के अन्दर, उत्तर प्रदेश के अन्दर या कुछ और राज्यों के अन्दर हर साल बाढ़ आती है और करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट होती है। फसल नष्ट होती है। मकान बरबाद होते हैं। जानवर बह जाते हैं और लोग डूबते हैं, मरते हैं। बिहार और यू० पी० की जो स्थिति होती है, वह तो आप लोग जानते ही हैं। अखबारों में हर साल पढ़ते होंगे। लेकिन इस साल जैसी बाढ़ आई बहुत दिनों तक ऐसी बाढ़ हमारे सूबे में नहीं आई थी। यों तो उत्तरी बिहार में बाढ़ हर साल आया करती है लेकिन दक्षिणी बिहार में कम आती थी। इस साल दक्षिणी बिहार भी अछूता नहीं रहा और पटना जिले में, गया जिले में, हजारी बाग जिले में बहुत भयानक बाढ़ आई और पटना के बह जाने का खतरा उत्पन्न हो गया था। अगर एक फुट भी पानी ज्यादा हो गया होता तो पूरा पटना शहर जहां की आबादी 4 लाख से ज्यादा है, बह जाता। तो यह समस्या आई। आप जानते हैं कि शहर में पानी घुस गया। लोग परेशान थे। सरकार की ताकत पूरी इसमें लग गई कि कैसे उसे नियंत्रित करें। यह स्थिति इस लिए है कि बिहार के अन्दर नदियां कम नहीं हैं। अगर उन नदियों को ठीक तरह से बांधा जाय तो बाढ़ से जनता की हिफाजत कर सकते हैं।

कोसी हमारे यहां की अभिशाप समझी जाती है। उस को बांधने की कोशिश की जानी चाहिए। गंडक, कमला, बलान, पुनपुन, मोरहर, डरधा आदि नदियां हैं। इन को अगर बांधा गया होता तो बाढ़ से सुरक्षा तो होती ही, उस से काफी सिंचाई का काम ले सकते थे। हमारे सूबे में जो पिछली बार इतना बड़ा अकाल आया उस से भी छुटकारा मिल सकता था। लेकिन अभी तक वह चीज हुई नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम उन तमाम नदियों को बांधें। फ्लड कंट्रोल की स्कीम लागू करें ताकि इनको बांध कर के लोगों को बाढ़ से बचा सकें और साथ-साथ वहां सिंचाई का भी इंतजाम विभिन्न तरीकों से करें। इसके बाढ़ से भी बचेंगे और अकाल की हालत भी पैदा नहीं होगी। इस साल की बाढ़ में लगभग 1 लाख कच्चे मकान हमारे सूबे के अन्दर गिर गए। केवल पटना जिले में 40 से 50 हजार तक मकान क्षतिग्रस्त हुए। शहर के हजारों मकान गिरे। इस तरह की विपति हमारे यहां आई। सरकार ने उस का मुकाबला करने की कोशिश की। हम यह कहना चाहते हैं कि बाढ़ नियन्त्रण की कोई कारगर योजना वहां लागू की जाय और वहां की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बाढ़पीड़ितों की मदद के लिए, दस करोड़ रुपय की मांग की थी। खुद यहां की सरकार के प्रतिनिधि गए हुए थे इस बात को जांच करने के लिए कि बाढ़ का एक्सटेंट कितना है, वह कितनी विस्तृत है, कितने इलाकों में फैली हुई है। मेरे खयाल से मंत्री महोदय को सब मालूम होगा क्योंकि उपमंत्री जो बैठ हुए हैं सिद्धेश्वर प्रसाद जी, यह तो हमारे यहां के रहने वाले हैं। जिस इलाके में बाढ़ आई, उस का उन को अनुभव है। तो वहां की सरकार ने मांगा है दस करोड़ रुपये इन्होंने कहा कि एक करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे। तो यह तरीका बाढ़ पीड़ितों की मदद का नहीं है। तरीका यह होना चाहिये कि जब भी हमारे यहां कोई राष्ट्रीय विपत्ति आय— भूकम्प आये, बाढ़ आये—ये सब राष्ट्रीय विपत्तियां हैं—ऐसे मौके पर सरकार को अगर-मगर नहीं करना चाहिये, बल्कि पूरी ताकत से मदद करनी चाहिये तथा हम यह जरूर चाहेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा सारे हिन्दुस्तान के लिये बाढ़ नियन्त्रण योजना ऐसी बनाई जाय, जिस के द्वारा हम सचमुच बाढ़ को रोक सकें तथा करोड़ों की सम्पत्ति बरबाद होने से बच सकें और नदियों का इस्तेमाल हम सिंचाई के लिये करें ताकि अमरीका के सामने हमें झोली न फैलानी पड़े, हमारे प्रधान मंत्री को या दूसरे मंत्रियों को जानसन साहब के सामने जाकर साष्टांग दण्डवत् करने की

[श्री रामवतार शास्त्री]

आवश्यकता न पड़े । इस बात की क्षमता हमारे देश में है कि हम नदियों को बांध कर उन को सिचाई के काम में लगा सकते हैं ।

SHRI S. KUNDU (Balasore) : This discussion should have come much earlier, better late than never.

In my part of the country, in my constituency, in my State, a grue some tragedy was witnessed in the form of these floods and then after two months there was the cyclone. I do not say that this is in any way graver than Koyna, it is all tragedy, which has completely enveloped all the people of India as such.

The floods which came in the month of September in my district of Balasore and in Mayurbhanj in the Swarnarekha and Burhabalanji was unprecedented. In 14 hours there was a rainfall of 18". At that time there was high tide in he sea, and the rain water was so heavy that it could not be discharged. People had not seen such floods in a hundred years, in living memory. I have got photographs of the flooded area, from which you can imagine what a horrible tragedy it was.

The people who were cating found that some water was coming, then their thalis started floating, in half an hour the houses started falling. People, cattle, everything was swept away by high floods. Much before any relief could reach there, the devastation, damage, was done. Therefore this is one of the greatest tragedies.

The area affected is 15,000 square miles, the population affected is 15 lakhs. The report is that more than 100 people have died in the floods, forgetting the 800 people who dies in the cyclone. Ten thousand villages have been affected, and many thousands of villages have been completely swept away. I was in hospital that time, and I had written a letter to Dr. K. L. Rao and also the Prime Minister. It is good that Dr. K. L. Rao, along with me, visited my constituency on 21st September.

As the saying goes, there was water, water everywhere, but not a drop to drink. There is so much abundance of water in my State, but we have not been able to channelise them for irrigation. One-tenth of the total rivers of India flows in my State. If you can harness it properly, this water will be useful for irrigation purposes, and Orissa can supply food to the whole of India. The plan for the development of the Swarnarekha-Burhabalanji basin has been lying in the cupboard of the Government for the last ten years. Investigation and flood control are inter-connected. If you want to do anything about flood control, naturally you block certain water by dam and you divert it for irrigation. Therefore, when you take up this question, we have been hammering on the Government that these projects should be taken, namely these projects which will irrigate about seven lakh acres of paddy land, and which would save permanently the flood devastation caused by the treacherous river the river of sorrow, that is, this Subarnarekha.

The hon. Minister had written to me a letter and he has spelt out some action which he was going to take. There was the national highway which the Government have built, and this national highway also was the cause of obstacle because it kept the water level high. He has also spelt out that there must be some sort of Investigation Division which will investigate into these flood measures and irrigation measures. He has also suggested some irrigation schemes in that letter. I would like to know from the young Minister who has taken charge—Dr. K. L. Rao is not here unfortunately—as to how he is going to implement them.

Another thing is, in such calamities, the attitude has been one of Centre versus the States. We have to forget all these. We have been pleading that at the level of the Centre there must

be some allotment for relief operations in the budget. Some crores of rupees must be allotted for relief operations, and a relief squad at the Centre with the defence personnel should be maintained. Immediately there is flood, the defence personnel must be able to go there with boats and other rescue equipment, and commence rescue operations, along with the supply of food, clothing, etc. I cannot imagine, during this cold winter, how the people of my State and also in Koynanagar and other places would be living: they would be shivering in this biting cold, without food, clothing and shelter. If the agency which I suggest is built up, we can easily make relief available to them.

The difficulty is this. Whenever there is a grant given by this Government, it is always a matching grant. Suppose it sanctions Rs. 1 crore, they want the State Government also to give Rs. 1 crore. Sometimes, the State Government is so poor that it cannot give money because it does not have money; it does not have enough resources. Therefore, it is necessary that allotment should be made for Central relief in the general budget and the Irrigation Minister will take up the matter with the Finance Minister and see that this is done.

There is one more thing. After this flood devastation, which has completely damaged Adra, Balasore and Mayurbhanj and other parts in my State, there is a new awareness among the people to grow more food and a new awareness also among the young people who have been elected as Sarpanches and as other officers. They are doing a dedicated work. When I was touring in my constituency, a Santhal came and said that he wants to grow wheat in his village called Bathnoti, because he has learnt it from a Marwadi shopkeeper, I was astonished. This is an example of the awareness coming from a Santhal, who wants to grow more paddy and wheat but he does not get any initiative from the officers. He does not get initiative from the voluntary or social organisations. Therefore, when there is national calamity, when there is flood or any other damage like that, what I feel is that the agricultural units should be built up completely on a new pattern and new village units should be built up, and for that, a complete lay-out and design should be given from the Central Government.

What I find at the time of the national calamities like flood and cyclone is, when people read this news, say, at Delhi, then, they start collecting relief funds etc., for helping the afflicted, say in Orissa or Koynanagar. Now, I say that this should not be left completely to the care of individual persons. What I suggest is that the Central Government and the Information and Broadcasting Ministry must have a forum, and immediately when there is a cyclone or flood or earthquake, this forum must go and take the photographs and use the television and radio and print leaflets and circulate them to everybody and through such a forum or national committee, the relief funds should be collected.

With these words, I plead with the minister to pay particular attention to the sufferings of the people in my area, in Balasore and Mayurbanj and also in the areas in West Bengal just now mentioned by my friend, Shri Samar Guha.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Sir, Last September, the districts of Balasore, Puri, Cuttack and Mayurbanj in Orissa were very much affected by the floods. Therefore, I fully agree with the suggestion of my friend, Mr. Gupta, to have a long-range programme, a master plan, for each State, so that the flood problem can be tackled permanently.

Flood and drought have still remained a constant feature of Orissa. After the construction of the

[Shri Chintamani Panigrahi]

Hirakud reservoir, the floods in Mahanadi have been controlled to a certain extent. But there were different stages of flood control planning so far as Mahanadi is concerned. After the first stage was ever, the other stages have been left over. There was a proposal to divert some waters of Mahanadi to Chilka through Manibhadra, and Gania barrage schemes to provide irrigation facilities to vast areas in Bolagarh—Begunia, Daspalla, Banpur, Ranpur, Khurda and Brahmagiri. That programme has not yet been implemented.

During the last floods, the hon. Minister for Irrigation and Power was kind enough to visit the flood-affected areas. An expert team which visited the areas came to certain conclusions, namely, there were insufficient facilities for drainage of flood water. Secondly, wherever a national highway is passing, it acts as an obstruction and more escapes should be there in national highways for discharge of flood water. So far as the area between Subarnarekha and Burrabalang and Brahmani and Baitaraui are concerned that must be fully protected from flood. In Cuttack flood has been controlled to a certain extent but Balasore and Mayurbanj district are in constant danger of flood. The control of floods in Subarnarekha is a joint work between the Governments of West Bengal and Orissa and Bihar. What has happened to all these suggestions made by the expert team? They should be implemented immediately.

Another danger which they referred to was the erosion of many villages near the river embankments. I want to bring to the notice of the minister that Kantille and Padmavati villages, which are historically most important places, are going down today into the lead of the Mahanadi river, because every year, the river is eroding and the villages are going into the bed of the river. I want to know what steps Government have taken to implement there recommendations of the expert committee and devise ways to protect these villages.

From a fast-developing State, Orissa has recently turned into a relief State, depending only on relief. For 20 years, this State was neglected. Only recently when it had started moving fast, it has turned into a relief State. The report of the minister says that the Orissa, Government took adequate measures to provide relief to the flood affected people. This is incorrect. The people are suffering most. The Central Government should do its best to solve the flood and drought problem of Orissa including drinking water supply, so that there is a permanent solution.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया): सभापति महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से आता हूं जोकि सदा से बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है और जहां कि विकास कार्य भी बहुत कम ही हुआ है। हमारे प्रदेश के पूर्वी जिले जैसे बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर और पश्चिमी बिहार के जिले जैसे आरा, छपरा आदि इस बाढ़ के प्रकोप से आमतौर पर प्रभावित रहते हैं। इन क्षेत्रों में यह बाढ़ की बीमारी एक मुतकिल बीमारी है और करीब करीब हर साल ही यह बाढ़ वहां पर आती है तो भी यह दु:ख की बात है कि हम इस बाढ़ के ऊपर स्थायी तौर पर नियन्त्रण नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार ने इस बाढ़ की भीषण समस्या को देखते हुए एक भिडे कमेटी की स्थापना की थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस भिडे कमेटी की रिपोर्ट हमें अभी तक नहीं मिली है ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर एक स्थायी तौर पर कम से कम इन पूर्वी जिलों के लिए कोई एक रास्ता निकाला जाय।

विशेष कर जिस जिले से मैं आता हूं वह हमारा बलिया जिला, करीब दो तिहाई जिला, यह गंगा, घाघरा और टोंस नदी के बीच में स्थित हैं। हम देखते हैं कि बाढ़ के कारण प्राय: प्रतिवर्ष ही हजारों घर बरबाद हो जाया

करते हैं, मवेशी बह जाया करते हैं तो मैं चाहूंगा कि उस भिडे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस समस्या का कोई परमानेंट हल निकाले और जो भी सहायता आवश्यक हो वह सहायता भी उपलब्ध करे।

बाकी जो कोयनानगर में भूकम्प के कारण भारी तबाही आई है और जान व माल को भारी मात्रा में क्षति पहुंची है उसके लिए पीड़ित और क्षतिग्रस्त लोगों को जो सहायता पहुंचाने के बारे में वहां पर सुझाव दिये गये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव): सभापति महोदय, मुझे आप ने केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देने को कहा है। एक मिनट में वैसे मैं अपनी सारी बात कह तो न सकूंगा लेकिन बहरहाल जो भी सम्भव है वह सदन की सेवा में पेश करे देता हूं।

मुझे यह दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई तो पुराने जितने सिंचाई के साधन थे उन सब पुराने साधनों की उपेक्षा की गई और नये सिंचाई के साधनों पर ही इस देश के किसानों को निर्भर कराया गया। मेरी समझ में सब से बड़ी भूल सरकार से यह हुई है कि सिंचाई के पुराने साधनों को उपयोग में नहीं लाई और नये साधनों के ऊपर किसानों को निर्भर किया गया जिसका कि नतीजा आज सरकार को भुगतना पड़ रहा है और यह सिंचाई की समस्या को हम हल नहीं कर पा रहे हैं।

छोटी सिंचाई योजना पर सरकार कम ध्यान दे रही है और बड़ी सिंचाई योजनाओं पर अधिक ध्यान दे रही है। वह जितने कुएं, तालाब वगैरह हैं उन सब की उपेक्षा हो रही है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है रहट हैं नहीं।

साथ-साथ मैं यह भी बतलाऊं कि बाढ़ के बाद से बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां न तो नहर जा सकती हैं न कुएं ही बन पाते हैं और न ही नलकूप लग पाते हैं। जो कछार ऐरिया है, जहां बाढ़ रुक गयी है वहां की जमीन पर न तो कुएं बन सकते हैं और न ही नलकूप लग सकते हैं। कछार के इलाके की हालत बड़ी चिन्ता-जनक हो गई है। उस के लिए सरकार कौन सी स्कीम बना रही है? वहां पर सिंचाई के कौन से साधन सरकार सुलभ करने जा रही है? मैं चाहूंगा कि सरकार लघु सिंचाई योजनाओं पर पुन: ध्यान दे। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय जब बहस का जवाब देंगे तब वह इस बारे में राज्यवार ब्यौरा देते हुए बतलायेंगे कि यह ट्यूबवैल का वितरण किस तरीके से हुआ है।

SHRI D. D. JENA (Bhadrak): *Spoke in Oriya.*

SHRI S. KUNDU: In one or two sentences I will give the gist of what the hon. Member has said in Oriya in his maiden speech. He said that the Centre must give more and more assistance to States like Orissa in flood prevention work and irrigation projects. He added that each Member of Parliament must donate Rs. 31 to the National Relief Fund. He said that he has his sympathies for the tragedies that take place in other areas also.

SHRI S. C. SAMANTA (Tamluk): My hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta demanded that there should be overall survey of the flood damages in the country and, in that connection, he referred to Delhi also. The Najafgarh canal in Delhi has been investigated by experts. There was a flood in Midnapur district. I think it was in 1960 when the then hon. Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru went and visited the flood-affected area. He also constituted an expert committee under the chairmanship of Shri Man Singh. Shri Man Singh has submitted a report not only about Midnapur district but the whole of West Bengal. But nothing has been done as yet for implementing the recommendations of

[Shri S. C. Samanta]

the committee. So, I would like to know from the hon. Minister what has been done about the Man Singh Committee report.

श्री रामानन्द शास्त्री (बिजनौर) : मैं पिछले दस साल से कहता आ रहा हूं कि घाघरा से बाराबंकी, गोंडा आदि को जबर्दस्त नुकसान होता है, इसमें जो बाढ़ आती है उससे धन जन की बड़ी हानि होती है। हर साल हजारों गांव वहां नष्ट हो जाते हैं और धन जन की बड़ी हानि होती है। घाघरा बाराबंकी, गोंडा, होते हुए बलिया और छंपरा की ओर जाती है। बाराबंकी और गोंडा जिलों की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पिछले दिनों वहां पर हजारों गांव नष्ट हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि आगे जो योजना बने उस में आप इसका भी ध्यान रख।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है उनको हृदय में से धन्यवाद देता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त ने कहा है कि बाढ़ की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। पहले पहल हमारे देश में 1954 में स्वतन्त्रता के बाद भयंकर बाढ़ आई थी और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने उसके बाद से इस समस्या पर इसी दृष्टि से विचार किया है। ऐसी बात नहीं है कि पिछले इतने वर्षों में बाढ़ नियन्त्रण की कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बनाई गई है। मैं बतलाना चाहता हूं कि और काफी काम हुआ है और अब तक करीब 170 करोड़ रुपया हम खर्च कर चुके हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं हमारा देश मौनसूनी देश है। देश के किसी हिस्से में पानी बिल्कुल नहीं पड़ता है और फिर उसी हिस्से में ऐसा होता है कि अचानक इतनी वर्षा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। बिहार का उदाहरण अभी माननीय श्री रामावतार शास्त्री ने दिया है। पिछले साल वहां अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद अचानक इतना पानी पड़ा कि पटना में बाढ़ आ गई। और जगह भी यही स्थिति है। कोसी, दामोदर, महानदी आदि जो नदियां हैं वहां पर बाढ़ नियन्त्रण का काफी काम हुआ है और लाखों एकड़ जमीन को बाढ़ ग्रस्त होने से बचाया जा चुका है। 128 ऐसे शहर हैं जो बाढ़ की चपेट में आ जाते थे। उनकी रक्षा का प्रबन्ध किया जा चुका है।

इसमें सब से बड़ी बात साधनों की है। अगर हम देश में एक साल में बाढ़ नियन्त्रण की पूरी योजना को लागू करना चाहें तो कम से कम बारह सौ करोड़ रुपया हमें चाहिये। अभी तक लेकिन मैं बता चुका हूं कि हम इस पर केवल 170 करोड़ रुपया खर्च कर पाए हैं। अपने वित्तीय साधनों को देखते हुए ही हम काम कर सकते हैं। कई और भी गम्भीर समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं जिन के लिए रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले कोयना की चर्चा हो रही थी। मैं यह नहीं कहता कि बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्या ज्यादा गम्भीर है या भूकम्प पीड़ित लोगों की। मैं समझता हूं कि दोनों ही समस्यायें गम्भीर हैं। हमें अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए कोयना के लोगों को भी सहायता करनी है और बाढ़ पीड़ित लोगों को भी, फिर चाहे वे उड़ीसा के लोग हों या पश्चिमी बंगाल के हों या बिहार के हों या हिरयाणा के हों या किसी भी अन्य प्रान्त के हों। मद्रास में भी ऐसी ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मैं समझता हूं कि हमें साधनों की सीमा में ही इन सब कामों को करना है।

श्री कंवर लाल गुप्त ने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश का सर्वेक्षण करें। सारे देश का बाढ़ नियन्त्रण की दृष्टि से प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है। लेकिन जब हम किसी खास नदी पर बाढ़ नियन्त्रण की किसी योजना को लागू करना चाहते हैं तो वह प्रारम्भिक सर्वेक्षण

काफी नहीं होता है। तब अगर विस्तार में और और गहराई में जाने की जरूरत पड़ती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने स्वर्ण रेखा नदी से होने वाली हानि की ओर ध्यान दिलाया है। उसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। लेकिन और भी विस्तार में जाने की जरूरत है और उसके लिए राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जब उड़ीसा सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी तब उस योजना पर विचार किया जायगा और उसके बाद साधनों का सवाल पैदा होगा। जब साधनों की व्यवस्था हो जायगी तब बिहार सरकार, बंगाल सरकार की सहमति से केन्द्रीय जल योजना आयोग के विशेषज्ञों की देखरेख में उस विद्युत को आगे बढ़ाने की बात आयगी। उसी प्रकार से और भी दूसरी नदियां हैं।

दिल्ली की समस्या की ओर अभी श्री कंवर लाल गुप्त ने ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा है कि बीस वर्ष से यहां बाढ़ आ जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि इस प्रदेश में कोई काम ही नहीं किया गया है। ढांसा बांध 1962 में बनाया गया था जिस की वजह से काफी राहत मिली है। लेकिन एक दूसरी बात यह हो गई यहां जो कई झीलें थीं, जो गहरी जमीन थी उनको काट कर नाले से मिला दिया गया जिससे यह समस्या गम्भीर हो गई। और भी बुनियादी बातें हैं जिन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। एक यह है कि अगर किसी खास स्थान को बाढ़ से बचाने की बात सोची जाती है तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि दूसरे स्थानों पर पानी का दबाव अधिक न हो जाए और वे क्षेत्र क्षतिग्रस्त न हो जायें। दिल्ली को बचाने के लिये योजना बनायें तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। राजस्थान या हरियाणा या उत्तर प्रदेश को कोई नुकसान न पहुंचे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा।

एक बात रिलीफ को ले कर कही गई है। जहां तक सम्भव होता है साधनों की सीमा में रहते हुए बिहार हो या बंगाल हो, उड़ीसा हो या देश का दूसरा हिस्सा हो या दिल्ली हो केन्द्रीय सरकार रिलीफ के कामों को जरूर प्राथमिकता देने की कोशिश करती है। ऐसी बात नहीं है कि किसी किसी राज्य की उपेक्षा की जाती है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अमुक स्थान पर प्रधान मंत्री नहीं गई हैं या मंत्री महोदय नहीं गए हैं। जब भी सम्भव होता है प्रधान मन्त्री या सिंचाई मंत्री जाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले प्रधान मंत्री मिदनापुर गए थे। अब प्रधान मन्त्री के लिए शायद वहां जाना सम्भव नहीं हो सका है। जहां सम्भव होता है प्रधान मन्त्री जाती हैं या मेरे वरिष्ठ सहयोगी डा० राव जाते हैं या जो जो सिंचाई मंत्री रहे हैं जब भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हुई है उन्होंने जाने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो आवश्यक कार्रवाई होती है वह भी की जाती है।

हमारे देश में बड़ी-बड़ी नदियां हैं। इन नदियों का अथाह पानी है। इन से बाढ़ आ जाती है। उसकी वजह से काफी नुकसान होता है। धन जन की भी हानि होती है और कृषि भी नष्ट होती है। साधनों या दूसरी बातों का ध्यान रखते हुए यह जरूरी है कि हम एक एक कर इस काम को हाथ में लेकर इसको प्राथमिकता दें। लेकिन देखा गया है कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी में इस साल भयंकर बाढ़ आई है तो दूसरे साल गंगा में आ गई है और तीसरे साल यमुना में आ गई है। इस वास्ते बड़े पैमाने पर इस काम को सरकार ने करने की कोशिश की है। मैं माननीय सदस्यों को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर बाढ़ नियन्त्रण की योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया है कि बाढ़ के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए कुछ

सूचना-केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए, जहां से यह मालूम हो सके कि अमुक क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, या अमुक बांध पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है, ताकि उस क्षेत्र के निवासियों को समय पर सावधान किया जा सके। यह ठीक है कि इस से उन का पूरा बचाव नहीं हो सकता है, लेकिन यदि उन को चार पांच घंटे या एक दो दिन मिल जायें, तो वे अपने बचाव का कुछ प्रबन्ध तो कर सकते हैं। कुछ रोज पहले दिल्ली में एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार का एक केन्द्र लखनऊ, पटना और आसाम में भी बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि बाढ़-नियन्त्रण के सम्बन्ध में विभिन्न माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, सरकार उन पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार करेगी और इस बात का प्रयत्न करेगी कि जहां तक सम्भव हो सके, यथा शीघ्र बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं को कार्यान्वित किया जाये और लोगों को बाढ़ के प्रकोप से मुक्त रखा जाये।

मैं एक बार पुनः उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस चर्चा के दौरान अमूल्य सुझाव दिये हैं।

माननीय सदस्य, श्री सामन्त, ने मानसिंह कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के बारे में जो सूचना मांगी है, वह मैं बाद में दे दूंगा। जहां तक माननीय सदस्य, श्री मोलहू प्रसाद, का सम्बन्ध है, मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से है और वह सूचना मेरे पास अभी नहीं है।

श्री कंवरलाल गुप्त : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में दिये गये सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। मेरी शिकायत यह है कि इस सम्बन्ध में फाइव-यीअर प्लान्ज में जितने रुपये का प्राविजन किया गया हैं, उतना रुपया भी खर्च नहीं हुआ है और काफी रुपया बच गया है। आवश्यकता इस बात की है कि वह सारा रुपया ठीक प्रकार से खर्च हो और समय पर खर्च हो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि देर होने की वजह से काम बारिश में बह गया।

जब बाढ़ आती है, तो पानी ऊपर से पड़ता है, लेकिन दिल्ली, और खास तौर पर नई दिल्ली में, नीचे से भी बाढ़ आ रही है। मेरा तात्पर्य यहां के सब-सायल वाटर से हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस का भी ध्यान रखें।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That this House takes note of the statement laid on the Table by the Minister of Irrigation and Power on the 14th November, 1967, on the flood situation in the country."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A.M.

20.54 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 22, 1967/Pausa 1, 1889 (Saka).

104LSS/67—1010—18-3-68—GIPF.